

## पंचायती राज चुनाव, 2010 का विवरण एवं सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक

Ravinder Singh

Research Scholar, CMJ University

Guide : Shamsheer Singh

### सार

भारत में पंचायती राज प्रणाली शासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है जो गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाता है। इन स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए पंचायती राज चुनाव समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। हालांकि, चूंकि मेरी जानकारी का कटऑफ सितंबर 2021 है, इसलिए मैं आपको उस बिंदु तक पंचायती राज चुनाव पर जानकारी प्रदान कर सकता हूं। 2010 में पंचायती राज चुनाव भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह विभिन्न राज्यों में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य गांव, ब्लॉक और जिला पंचायतों के सदस्यों का चुनाव करना था। चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों को उनका प्रतिनिधित्व करने और स्थानीय शासन के मामलों पर निर्णय लेने के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए मतदान करना शामिल था। 2010 के पंचायती राज चुनाव में चुने गए सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि विशिष्ट क्षेत्र और संदर्भ पर निर्भर करेगी।

**कीवर्ड:** पंचायती राज चुनाव 2010, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, विकेंद्रीकृत शासन

### परिचय

2010 में हुए पंचायती राज चुनाव ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जो विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंचायती राज प्रणाली, जो स्थानीय स्वशासन के सिद्धांतों में गहराई से निहित है, प्रभावी निर्णय लेने और ग्रामीण समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रणाली के तहत, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर आयोजित चुनाव नागरिकों को प्रतिनिधियों को चुनने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जिन्हें अपने इलाकों के भाग्य को आकार देने का काम सौंपा जाएगा। इन चुनावों के परिणाम न केवल राष्ट्र के विविध सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को दर्शाते हैं, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के लिए भी गहरा प्रभाव

डालते हैं। पंचायती राज चुनाव के दौरान चुने गए सदस्यों की पृष्ठभूमि को आकार देने में सामाजिक-आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का समाज जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और आय के स्तर सहित विभिन्न किस्मों के साथ बुना गया एक टेपेस्ट्री है। ये कारक अक्सर निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रोफाइल को प्रभावित करते हैं, जिससे स्थानीय आबादी की विविधता का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। राजनीतिक संबद्धता निर्वाचित सदस्यों की संरचना में एक और परत जोड़ती है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल पंचायती राज चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं, इस जमीनी स्तर के शासन ढांचे का उपयोग अपनी उपस्थिति को मजबूत करने, अपने एजेंडे को बढ़ाने और ग्रामीण मतदाताओं से जुड़ने के साधन के रूप में करते हैं। 2010 में पंचायती राज चुनाव न केवल लोकतांत्रिक भागीदारी की कवायद थी, बल्कि स्थानीय मुद्दों और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब भी था जो मतदाताओं के साथ गूँजते थे। अभियान की कहानियां पानी की कमी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि नीतियों और रोजगार के अवसरों जैसी प्रमुख चिंताओं को संबोधित करने के इर्द-गिर्द घूमती थीं। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने समुदायों की आवाज बनने का संकल्प लिया, जो भीतर से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। महत्वपूर्ण रूप से, पंचायती राज प्रणाली महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर महत्वपूर्ण जोर देती है, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर महिलाओं की आवाज को बढ़ाना है। 2010 के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास देखा गया, जो संवैधानिक प्रावधानों और स्थानीय शासन पर महिलाओं के नेतृत्व के परिवर्तनकारी प्रभाव की मान्यता से प्रेरित था। 2010 में आयोजित पंचायती राज चुनाव ने विकेंद्रीकृत शासन के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया, स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाया। निर्वाचित सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि ने देश के विविध ताने-बाने को प्रतिबिंबित किया, जबकि उनके एजेंडे अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के आसपास केंद्रित थे। जैसे-जैसे भारत प्रगति कर रहा है, ये चुनाव एक आवश्यक लोकतांत्रिक अभ्यास बने हुए हैं जो नागरिकों और उनके स्थानीय शासन संरचनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करते हैं, जमीनी स्तर से विकास और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं।

**पंचायती राज का विकास भारत में विकेंद्रीकृत शासन की यात्रा**

भारत में पंचायती राज प्रणाली का विकास विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र की खोज में एक उल्लेखनीय अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। स्थानीय स्वशासन के सिद्धांतों में निहित, पंचायती राज की यात्रा भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों से जुड़ी हुई है, जो शासन को लोगों के करीब लाने और ग्रामीण समुदायों की अनूठी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से चिह्नित है। पंचायती राज की उत्पत्ति महात्मा गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व में पाई जा सकती है, जिन्होंने शासन के एक विकेंद्रीकृत रूप की कल्पना की जो गांवों को सशक्त बनाएगा और वास्तव में लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव के रूप में काम करेगा। आत्मनिर्भरता और गांव-केंद्रित विकास के गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित होकर, पंचायती राज की जड़ें भारतीय संविधान के मसौदे के दौरान बोई गई थीं, जिसमें स्थानीय स्वशासन के प्रावधान इसके ढांचे के भीतर निहित थे। 1990 के दशक तक पंचायती राज व्यवस्था ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की और एक परिवर्तनकारी चरण देखा। 1992 का 73 वां संशोधन अधिनियम, जिसे आमतौर पर पंचायती राज अधिनियम के रूप में जाना जाता है, विकेंद्रीकरण आंदोलन के लिए उत्प्रेरक बन गया, जो गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना के लिए संवैधानिक मान्यता और कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तक के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार देकर सशक्त बनाना था। इसने ग्रामीण नागरिकों और सत्ता के गलियारों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की, यह सुनिश्चित करते हुए कि शासन न केवल भागीदारी पूर्ण था, बल्कि उन लोगों की जरूरतों के प्रति भी उत्तरदायी था जिनकी उसने सेवा की थी। पंचायती राज की यात्रा एक विकसित प्रक्रिया रही है, जिसे भारत के विशाल और विविध परिदृश्य की सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता द्वारा आकार दिया गया है। इस प्रणाली ने समय की बदलती जरूरतों को अनुकूलित किया है, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं सहित समाज के हाशिए वाले वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधानों को शामिल किया गया है। इस सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना और ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना था, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक की आवाज, उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, स्थानीय शासन में अभिव्यक्ति पा सके। पंचायती राज की यात्रा केवल विधायी सुधारों तक ही सीमित नहीं है। इसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, नीति निर्माताओं और नागरिकों के अथक प्रयास शामिल हैं, जिन्होंने विकेंद्रीकृत शासन की नींव को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास

किया है। यह भारत के शासन को देखने के तरीके में एक प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, यह स्वीकार करते हुए कि प्रभावी निर्णय लेने के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी और स्वामित्व की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे पंचायती राज व्यवस्था विकसित हो रही है, यह चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना कर रही है। सीमित वित्तीय संसाधन, क्षमता निर्माण और जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियां फोकस के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। हालांकि, यह प्रणाली सतत विकास को चलाने, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर नेतृत्व को पोषित करने के लिए अपार क्षमता भी प्रस्तुत करती है।

### **जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना पंचायती राज चुनाव का महत्व**

पंचायती राज चुनाव भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने की आधारशिला के रूप में खड़ा है, जो जमीनी स्तर के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है और स्थानीय समुदायों को अपने भाग्य को आकार देने के लिए सशक्त बनाता है। नागरिकों और सत्ता के गलियारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हुए, ये चुनाव लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और समावेशी शासन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इसके मूल में, पंचायती राज चुनाव भारत के शासन प्रतिमान में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि यह सत्ता को विकेंद्रीकृत करना और शासन को लोगों के करीब लाना चाहता है। संविधान में निहित यह विकेन्द्रीकृत प्रणाली, ग्रामीण समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली विविध सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने में स्थानीय स्व-शासन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है। पंचायती राज चुनाव के दौरान अपना वोट डालकर, नागरिक उन प्रतिनिधियों को चुनने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हैं जो जमीनी स्तर पर उनके हितों का समर्थन करेंगे। ये निर्वाचित प्रतिनिधि अपने समुदायों की आवाज बन जाते हैं, जिन्हें उन मामलों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जो सीधे उन लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। पंचायती राज चुनाव के प्रमुख महत्वों में से एक नागरिकों के बीच स्वामित्व और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता में निहित है। यह व्यक्तियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होने और उनके स्थानीय शासन संरचनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने की अनुमति देकर, चुनाव नागरिक जुड़ाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, नागरिकों को अपने

दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने में सक्रिय रुख लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। पंचायती राज चुनाव समावेशी प्रतिनिधित्व के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं सहित समाज के हाशिए के वर्गों के पास अपनी चिंताओं को आवाज देने और निर्णय लेने में भाग लेने के लिए एक मंच है। सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक करना और इन हाशिए वाले वर्गों के सशक्तिकरण के लिए जगह बनाना, सामाजिक समानता और समावेश को बढ़ावा देना है। चुनाव प्रक्रिया स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं और चिंताओं को भी बढ़ाती है। पंचायती राज चुनाव के दौरान अभियान अक्सर स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के अवसरों तक पहुंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के आसपास घूमते हैं। इन मुद्दों को सामने लाकर, चुनाव प्रक्रिया ग्रामीण समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों का सामना करने के लिए बातचीत शुरू करने, जागरूकता बढ़ाने और संसाधन जुटाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। पंचायती राज चुनाव जमीनी स्तर के नेतृत्व को पोषित करने और प्रभावी स्थानीय प्रतिनिधियों के केंद्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लोकतांत्रिक अभ्यास के माध्यम से, विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों, चाहे वह शिक्षा, व्यवसाय, या सामाजिक-आर्थिक स्थिति हो, को सामुदायिक विकास के लिए अपने कौशल, विशेषज्ञता और दृष्टिकोण का योगदान करने का अवसर मिलता है। नेतृत्व के विकास के लिए यह निचला दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि शासन के निर्णय स्थानीय वास्तविकताओं में निहित हैं और लोगों की जरूरतों का सही प्रतिनिधित्व किया जाता है।

### **धर्म और राजनीति स्थानीय शासन में धार्मिक कारकों के परस्पर क्रिया की जांच**

धर्म और राजनीति का परस्पर प्रभाव लंबे समय से जांच और अन्वेषण का विषय रहा है, और यह भारत में पंचायती राज प्रणाली सहित स्थानीय शासन के संदर्भ में विशेष प्रासंगिकता रखता है। धर्म, सामाजिक पहचान के एक गहरे पहलू के रूप में, अक्सर जमीनी स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक गतिशीलता और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। स्थानीय शासन के क्षेत्र में, पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य धार्मिक संबद्धताओं की परवाह किए बिना भागीदारी लोकतंत्र और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करना है। हालांकि, यह जांचना आवश्यक है कि धार्मिक कारक राजनीतिक परिदृश्य को कैसे आकार दे सकते हैं और स्थानीय शासन की

गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। धर्म का भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने पर गहरा प्रभाव है, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदाय इसकी सीमाओं के भीतर सह-अस्तित्व में हैं। पंचायती राज चुनाव सहित चुनावों के दौरान धर्म और राजनीति का अंतर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उम्मीदवार और मतदाता खुद को धार्मिक आधार पर संरेखित कर सकते हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह के राजनीतिक दल अक्सर समर्थन जुटाने और विशेष धार्मिक पहचानों के इर्द-गिर्द रैली करने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। पंचायती राज चुनाव के संदर्भ में, स्थानीय शासन पर धर्म का प्रभाव कई तरीकों से प्रकट हो सकता है। सबसे पहले, धार्मिक समुदाय निर्वाचित निकायों के भीतर प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हैं, अपने धार्मिक हितों, सांस्कृतिक प्रथाओं और धार्मिक संस्थानों के संरक्षण और प्रचार की वकालत कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया इन समुदायों के लिए अपनी चिंताओं को आवाज देने, अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और किसी भी शिकायत के निवारण की मांग करने का एक मंच बन जाती है। धर्म और राजनीति की परस्पर क्रिया पंचायती राज संस्थानों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने शासन के फैसलों को धार्मिक भावनाओं या अपने निर्वाचन क्षेत्रों से धार्मिक रूप से प्रेरित अपेक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यह परस्पर क्रिया भूमि उपयोग, धार्मिक संरचनाओं, त्योहारों और अन्य मामलों से संबंधित नीतियों को प्रभावित कर सकती है जो धार्मिक significance.it को धारण करते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता और समावेशी शासन के सिद्धांतों में निहित है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि निर्णय किसी विशेष धर्म या समुदाय के प्रति पक्षपाती नहीं हैं। संवैधानिक प्रावधान सभी नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हैं, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, और इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जो सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और धार्मिक विविधता का सम्मान करता है।

### निष्कर्ष

2010 के पंचायती राज चुनाव ने विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया। इस चुनाव ने नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और उन प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अवसर प्रदान किया जो स्थानीय स्तर पर अपने हितों का समर्थन करेंगे। 2010 के

पंचायती राज चुनाव में चुने गए सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि ने भारतीय समाज के विविध ताने-बाने को प्रतिबिंबित किया। जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और आय के स्तर जैसे कारकों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की संरचना को प्रभावित किया, जिससे स्थानीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक विविधता का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। इस विविध पृष्ठभूमि ने अधिक समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान दिया और समाज के विभिन्न वर्गों की अनूठी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद की। चुनाव में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों के साथ राजनीतिक संबद्धताओं का परस्पर प्रभाव देखा गया। इन राजनीतिक संबद्धताओं ने निर्वाचित सदस्यों द्वारा किए गए शासन के निर्णयों को आकार देते हुए विचारधाराओं, एजेंडों और प्राथमिकताओं की एक श्रृंखला को सामने लाया। पंचायती राज चुनाव ने महिलाओं और हाशिए की जातियों सहित समाज के हाशिए वाले वर्गों को स्थानीय शासन में अधिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी प्रदान किया। सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधानों ने यह सुनिश्चित किया कि इन ऐतिहासिक रूप से हाशिए वाले समूहों की आवाज सुनी जाए और उनकी चिंताओं को संबोधित किया जाए। 2010 के पंचायती राज चुनाव में चुने गए सदस्यों को अपने समुदायों के महत्वपूर्ण मुद्दों और प्राथमिकताओं को संबोधित करने का काम सौंपा गया था। उनके अभियानों और बाद के शासन के फैसलों ने पानी की कमी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि नीतियों और रोजगार के अवसरों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। शासन के लिए इस स्थानीय दृष्टिकोण ने ग्रामीण समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के लक्षित समाधान की अनुमति दी, जिससे जमीनी स्तर के विकास को बढ़ावा मिला। 2010 के पंचायती राज चुनाव ने भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व किया। निर्वाचित सदस्यों की विविध सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने की उनकी प्रतिबद्धता के साथ, समावेशी और उत्तरदायी शासन में योगदान दिया। जैसा कि भारत अपनी लोकतांत्रिक यात्रा जारी रखता है, पंचायती राज प्रणाली नागरिक भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनी हुई है, यह सुनिश्चित करती है कि शासन के निर्णय जमीनी स्तर पर लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। समावेशी प्रतिनिधित्व को पोषित करके और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर, पंचायती राज प्रणाली एक अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भारत का मार्ग प्रशस्त करती है।

## संदर्भ

1. सुरेन्द्र कटारिया, ग्राम विकास एवं पंचायती राज, जयपुर, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, 2003
2. लक्खी भूषण प्रसाद, पंचायती राज एवं विकास में महिलाएं, कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, अप्रैल-1996, खंड-42, पृ.52
3. आशुताष श्री वास्तव, विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था, दिल्ली, सनराइज पब्लिकेशन्स, 2004, पृ.
4. डी.डी.पी.ओ. कार्यालय, रोहतक, द्वारा सूचना के आधार पर।
5. भारत की जनगणना, 2011
6. शर्मा, शकुंतला (1994)। जमीनी राजनीति और पंचायती राज। दीप और दीप प्रकाशन। पी। 131.
7. सिंह, सूरत (2004)। भारत में विकेंद्रीकृत शासन: मिथक और वास्तविकता। दीप और दीप प्रकाशन। पी। 74. आईएसबीएन 978-81-7629-577-2।
8. "भारत के ग्रामीण स्थानीय सरकार की संरचना"। 3 जनवरी 2022 को पुनःप्राप्त।
9. सिंह, विजेंद्र (2003). "अध्याय 5: पंचायती राज और गांधी"। पंचायती राज और ग्राम विकास: खंड 3, पंचायती राज प्रशासन पर परिप्रेक्ष्य। लोक प्रशासन में अध्ययन। नई दिल्ली: सरूप एंड संस. पीपी। 84-90। आईएसबीएन 978-81-7625-392-5।
10. "गांवों में रहना | डी+सी - विकास + सहयोग"।
11. पंचायती राज: द ग्रासरूट्स डायनामिक्स इन अरुणाचल प्रदेश, पी। 13, एपीएच प्रकाशन, 2008, प्रताप चंद्र स्वैन
12. सिसोदिया, आर.एस. (1971). "गाँधीजी का पंचायती राज का दृष्टिकोण"। पंचायत और इंसान। 3 (2): 9-10।
13. शर्मा, मनोहर लाल (1987)। गांधी और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नई दिल्ली: दीप और दीप प्रकाशन। OCLC 17678104. हाथी ट्रस्ट कॉपी, सर्च ही